

प्रेषक,

दू.सी० ध्यानी,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्श,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग:

देहरादून : दिनांक 16 नवम्बर, 2004

विषय: रुड़की, जिला हरिद्वार में न्यायालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2004-05 में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-739/UHC/Con/Admin B. Sect/2004, दिनांक 12 अप्रैल, 2004 को सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि रुड़की जनपद हरिद्वार में न्यायालय भवन के निर्माण हेतु रु० 4,93,36,000/- के आगमन के विस्तृत टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु० 3,84,46,000/- (रुपये तीन करोड़ चौरासी लाख छिन्नलीस हजार मात्र) की धनराशि के लागत के आगमन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके विपरीत रु० 1,00,00,000/- (रुपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि के व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महानिबन्धक राज्यपाल विष्णुतिथित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) आगमन में उल्लिखित दरों का विवरण विभाग के अधीक्षण अधिपत्या द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का जो दरें शाहसुल ऑफ रेंट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा काजरा भाव से ली गई हों, को स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अधिपत्या का अनुमोदन आवश्यक होगा ।
- (2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगमन एवं मार्गचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, उपोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- (3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि नार्म के अन्तर्गत स्वीकृत है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।
- (4) एकमुश्त प्राविधानों का विस्तृत आगमन गठित कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त की जाय ।
- (5) उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन दी जाती है कि व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पंचेड क्लक, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय ।
- (6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भूतल-भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लिया जाय । निरीक्षण के पश्चात् निर्देश तथा निरीक्षण दिप्पनी के अनुरूप कार्य किया जाय ।
- (7) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।
- (8) आगमन में धनराशि जिस मद हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दररा में आवंटित न की जाय । उक्त स्वीकृति में साज-सज्जा की मदें सम्मिलित नहीं हैं ।

maharaj

- (9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में परीक्षण करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।
 - (10) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।
 - (11) कार्य पूर्ण कराये जाने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि की वित्तीय-एवं भौतिक प्रगति बताते हुये इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।
 - (12) धन का कोषागार से आहरण तीन बराबर किस्तों में ही किया जायेगा । एक किस्त के 80 प्रतिशत धन उपयोग में आने के बाद ही अगली किस्त का आहरण किया जायेगा और उपरोक्त धनराशि के पूर्ण उपभोग एवं कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण देने के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।
 - (13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.3.2005 तक सुनिश्चित कर लिया जाय । यदि उक्त अवधि तक किसी धनराशि का उपभोग सम्भव न हो तो उसकी सूचना शासन को दी जाय ।
 - (14) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/निर्माण एजेंसी पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी ।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-2005 की आय-व्यय की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "4059-लोकनिर्माण कार्य पर पुंजीगत परियोजना- 60-अन्य भवन-आयोजनागत-051-निर्माण-01-केंद्रीय आवासयोजना/केंद्र द्वारा पुरोक्थानित योजनाये-01-न्यायिक कार्य हेतु भवनों का निर्माण [50 प्रतिशत केंद्रीय]-24-ग्रहण निर्माण कार्य" के अन्तर्गत आयेगा ।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अरासकीय संख्या-1737/वि०अनु०-3/2004, दिनांक 04 नवम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहे हैं ।

भवदीय,

(दू.सौ.ध्यानी)
सचिव ।

संख्या-75-दो-(1)(1)/अतीम(1)/न्याय अनुभाग/2004-तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (संख्या एवं हकदारी) उत्तरांचल,माजरा, देहरादून ।
2. जिला जज, हरिद्वार ।
3. चरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार ।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
5. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
6. श्री एम० एम० पन्त, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन ।
7. नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन ।
8. वित्त अनुभाग-3/एन.आई.सी. /
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

moholirai
(आर०डी०पालीवाल)
अपर सचिव ।